

अनुक्रमणिका

क्र. सं.	टॉपिक का नाम
1.	'ट्रेसिंग द हेजी एयर 2026' रिपोर्ट में राजस्थान
2.	'प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना' में राजस्थान की स्थिति
3.	राजस्थान में खनिज उत्पादन की स्थिति
4.	न्यूज़ इन शॉर्ट्स 1. राजस्थान स्पोर्ट्स एक्ट, 2005 में संशोधन हेतु ड्राफ्ट जारी 2. चर्चा में - T-2408 3. सशस्त्र ड्रोन - 'प्रलय' 4. क्षुद्रग्रह (2021 DB5) का नया नाम - प्रमिश्का 5. निशानेबाज स्वीटी चौधरी 6. सब लेफ्टिनेंट रक्षिता राठौड़ 7. ईशविंदर सिंह : FIGSI के नए अध्यक्ष
5.	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI): उदय शुभंकर
6.	पृथ्वी अवलोकन उपग्रह: EOS-N1 (अन्वेषा)
7.	रेबीज: अधिसूचित बीमारी (नोटिफायबल डिजीज) घोषित
8.	सुपरकंप्यूटर संचालित पहला सिमुलेशन
9.	राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय : सकल घरेलू उत्पाद अनुमान
10.	पंखुड़ी पोर्टल
11.	विश्व हिंदी दिवस, 2026: 10 जनवरी
12.	जिन्सन जॉनसन : भारतीय धावक
13.	न्यूज़ इन शॉर्ट्स 1. सुरेश कलमाड़ी: निधन



राजस्थान परिदृश्य

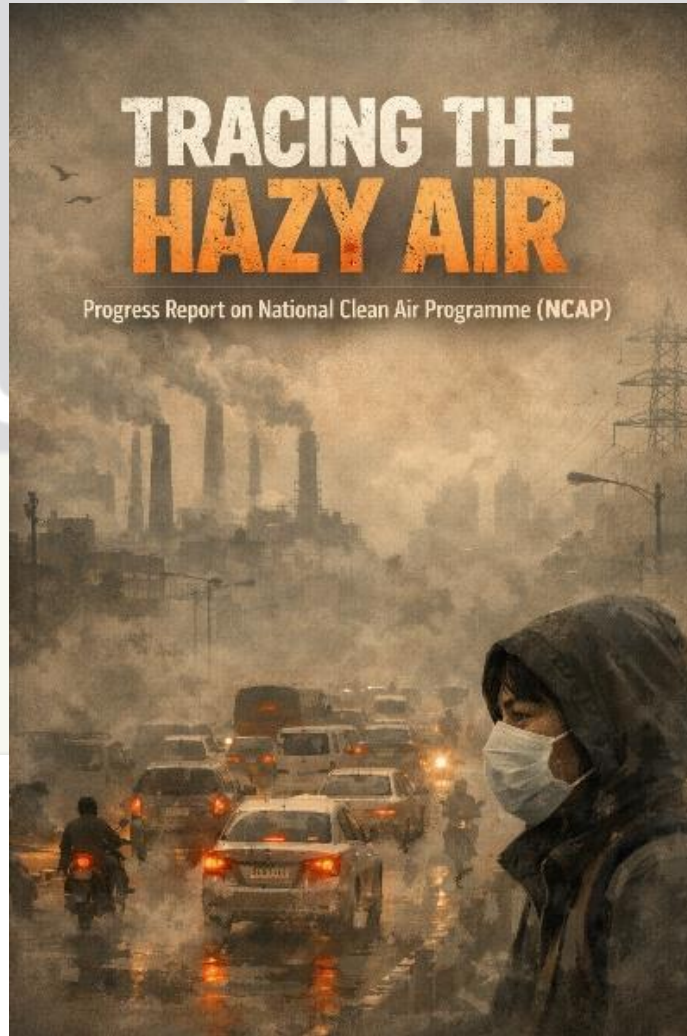


'ट्रेसिंग द हेजी एयर 2026' रिपोर्ट में राजस्थान



चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (CREA) द्वारा देश में व्याप्त वायु प्रदूषण संबंधी रिपोर्ट 'ट्रेसिंग द हेजी एयर 2026' जारी की गई।



मुख्य बिन्दु:

- रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा संचालित नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (NCAP) वायु प्रदूषण को रोकने में विफल रहा है।

--2--

- रिपोर्ट में देश के 4041 शहरों में PM2.5 स्तर का मूल्यांकन किया गया।
- **राजस्थान की स्थिति** : देशभर में दूसरा सबसे प्रदूषित राज्य। (प्रथम - उत्तर प्रदेश)
- राजस्थान के 158 शहर नॉन-अटेनमेंट (लगातार प्रदूषित) की श्रेणी में हैं।
- PM2.5 प्रदूषण के मामले में भिवाड़ी देश का 7वाँ सर्वाधिक प्रदूषित शहर है वहीं PM10 के प्रदूषण स्तर में भिवाड़ी देश में 9वें स्थान पर है।
- देश में PM10 प्रदूषण के शीर्ष 50 शहरों में से 18 शहर (श्री गंगानगर - 6th, बीकानेर - 8th) राजस्थान के हैं वहीं PM2.5 में सर्वाधिक 61 प्रदूषित शहरों में राजस्थान के 17 शहर शामिल हैं।

नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (NCAP)

- **लॉन्च** : पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा 24 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 130 शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से जनवरी, 2019 में NCAP लॉन्च किया गया।
- **NCAP का शुरुआती लक्ष्य** : वर्ष 2017 को आधार वर्ष मानते हुए वर्ष 2024 तक प्रमुख वायु प्रदूषकों; PM2.5 और PM10 की सांद्रता को 20 से 30 प्रतिशत तक कम करना था।
- लेकिन वर्ष 2022 में केंद्र सरकार ने इस कार्यक्रम के लक्ष्य में संशोधन कर दिया। नये लक्ष्य के मुताबिक वर्ष 2026 तक पार्टिकुलेट मैटर (PM) की सांद्रता में 40 प्रतिशत तक की कमी करना है।
- **PM2.5** - 40 माइक्रोग्राम (μg)/प्रति घन मीटर।
- **PM10** - 60 माइक्रोग्राम (μg)/प्रति घन मीटर।
- **'NCAP 2.0' कार्यक्रम** : वर्ष 2025-26 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) का पहला चरण समाप्त हो जायेगा। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय इस कार्यक्रम का दूसरा चरण लागू करेगा।

'प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना' में राजस्थान की स्थिति

चर्चा में क्यों?

- राजस्थान में दिसंबर, 2025 तक 'प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना' के तहत 1,23,701 रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाए जा जा चुके हैं।

PM Surya Ghar
Muft Bijli Yojana

- Free electricity for households.
- Reduced electricity costs for the government.
- Increased use of renewable energy.
- Reduced carbon emissions.

मुख्य बिन्दु:

- राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान का स्थान : पाँचवाँ।
- लक्ष्य : इस योजना के तहत राजस्थान द्वारा वर्ष 2027 तक 5,00,000 घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना:

- पूरा नाम : पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना।
- लॉन्च : 13 फरवरी, 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा।

Daily Current Affairs

Date : 10 January, 2026



- **उद्देश्य :** रूफटॉप सौर पैनलों की स्थापना की सुविधा के द्वारा घरों को मुफ्त बिजली प्रदान करना।
- **लक्ष्य :** मार्च, 2027 तक एक करोड़ घरों में सौर ऊर्जा की आपूर्ति करना।
- राज्य सरकार ने अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 'एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति-2024' जारी की है, जिसमें रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने के लिए नेट मीटरिंग, ग्रॉस मीटरिंग के साथ-साथ वर्चुअल नेट मीटरिंग एवं गुप नेट मीटरिंग के प्रावधान किए गए हैं।

फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:

राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024:

- राज्य सरकार द्वारा इस नीति की अधिसूचना 04 दिसंबर, 2024 को जारी की गई।
- **नीति की अवधि:** यह नीति अधिसूचना की तारीख से प्रभावी है और 29 मार्च, 2029 तक या किसी अन्य नीति द्वारा प्रतिस्थापित करने तक लागू रहेगी।

लक्ष्य:

- नीति का उद्देश्य राज्य में वर्ष 2029-30 तक 1,25,000 मेगावाट (125 गीगावाट) अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लक्ष्य को प्राप्त करना है।

125 गीगावाट का विभाजन:

क्रम	उत्पादन का प्रकार	लक्षित क्षमता
1.	सौर (Solar)	90,000 MW
2.	पवन और हाइब्रिड (Wind & Hybrid)	25,000 MW
3.	हाइड्रो, पंप स्टोरेज प्लांट (PSP), बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम	10,000 MW

- **नोट:** राजस्थान द्वारा परंपरागत एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से 54,000 मेगावाट से अधिक विद्युत क्षमता के लक्ष्य को वर्ष 2031-32 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।

--5--

राजस्थान में खनिज उत्पादन की स्थिति

चर्चा में क्यों?

- राजस्थान में प्री-एम्बेडेड ब्लॉकों की नीलामी के तहत आवश्यक अनुमतियाँ प्राप्त कर 8 मेजर मिनरल ब्लॉक के ऑक्शन प्रक्रियाधीन है, वहीं माइनर मिनरल के 62 ब्लॉक और मेजर के 5 ब्लॉक चिह्नित किए गए हैं।

मुख्य बिन्दु:

- अहमदाबाद में आयोजित राष्ट्रीय खनिज चिंतन शिविर के दौरान राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में जानकारी दी गई।
- राजस्थान प्री-एम्बेडेड ब्लॉकों की नीलामी करने वाला देश का पहला राज्य है।
- **प्री-एम्बेडेड क्लियरेन्स** : मिनरल ब्लॉकों की नीलामी से पहले ही आवश्यक अनुमतियाँ प्राप्त कर ब्लॉक की नीलामी करने की प्रक्रिया को प्री-एम्बेडेड क्लियरेन्स कहा जाता है।
- केंद्रीय खान मंत्रालय ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन कर सभी राज्यों को नीलामी के लिए कम से कम पाँच ब्लॉकों को आवश्यक सभी अनुमतियों के साथ तैयार करने के निर्देश जारी किए गए।
- इन नीलामियों के लिए राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट (RSMET) को प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट के रूप में नामित किया गया है।

फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स (आर्थिक समीक्षा - 2024-25)

राजस्थान में खनन क्षेत्र:

- राजस्थान खनिज संसाधनों के सन्दर्भ में भारत के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक है, यहाँ 81 प्रकार के खनिजों के भंडार हैं, जिनमें से 58 खनिजों का खनन किया जाता है।

Daily Current Affairs

Date : 10 January, 2026



- राजस्थान सीसा एवं जस्ता अयस्क, सेलेनाइट और वोलेस्टोनाइट का एकमात्र उत्पादक राज्य है, वहीं चाँदी, कैल्साइट एवं जिप्सम के उत्पादन में देश में अग्रणी है।
- राजस्थान बॉल क्ले, फॉस्फोराइट, गेरू, स्टीटाइट, फेल्सपार और फायर क्ले के राष्ट्रीय उत्पादन में शीर्ष पर है।
- राजस्थान संगमरमर, बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट जैसे आयामी पत्थरों के साथ-साथ सीमेंट-ग्रेड और स्टील-ग्रेड चूना पत्थर का एक प्रमुख उत्पादक राज्य है।
- वर्ष 2024-25 में खान एवं भूविज्ञान विभाग हेतु ₹9,500 करोड़ का राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

राजस्थान खनिज नीति - 2024

- **जारी** - 04 दिसंबर, 2024 को।
- राजस्थान खनिज नीति-2024 का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण एवं सामुदायिक कल्याण सुनिश्चित करते हुए आर्थिक विकास के लिए राज्य के प्रचुर खनिज संसाधनों का लाभ उठाते हुए टिकाऊ, पारदर्शी और जिम्मेदार खनिज विकास को बढ़ावा देना है।

मुख्य विशेषताएँ:

- **आर्थिक विकास और निवेश:** खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना, निवेश आकर्षित करना और राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) में इस क्षेत्र के योगदान को बढ़ाना।
- **रोजगार सृजन:** वर्ष 2047 तक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से 1 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
- **स्थिरता और ई.एस.जी. अनुपालन:** शून्य अपशिष्ट खनन, पर्यावरण अनुकूल तकनीकों और अपशिष्ट प्रबंधन रणनीतियों को लागू करना।
- **प्रौद्योगिकी एकीकरण:** उन्नत अन्वेषण तकनीकों, AI आधारित निगरानी और डिजिटल प्रशासन अपनाकर पारदर्शिता सुनिश्चित करना।

--7--

Daily Current Affairs

Date : 10 January, 2026



- **अवैध खनन शमन:** GPS- आधारित ट्रैकिंग, जियो-फेंसिंग और रीयल-टाइम निगरानी का उपयोग कर अवैध गतिविधियों को रोकना।

प्रमुख पहल :

- वर्ष 2047 तक खनिज निष्कर्षण को 58 से बढ़ाकर 70 तक करना।
- पूर्व-निर्धारित स्वीकृति के साथ 50 प्रमुख खनिज ब्लॉकों की नीलामी।
- खनन रियायत क्षेत्र को वर्ष 2047 तक राज्य की कुल भूमि के 2 प्रतिशत तक बढ़ाना।
- स्वच्छ ऊर्जा के समर्थन में रणनीतिक और महत्वपूर्ण खनिजों (जैसे - लिथियम, रेयर अर्थ एलीमेंट्स) को बढ़ावा देना।
- खनिज संसाधनों में मूल्य संवर्धन और अनुसंधान हेतु एक राज्य खनन कंपनी की स्थापना करना।

अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु:

राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट (RSMET)

- **गठन :** वर्ष 2020 में।
- **उद्देश्य :** राजस्थान में उपलब्ध खनिज भण्डारों की वैज्ञानिक तरीके से खोज व खनन में आधुनिक तकनीक का उपयोग, अनुसंधान, शोध, कौशल विकास व राजस्व बढ़ोतरी सहित इससे जुड़ी गतिविधियों का बेहतर संचालन और मोनेटरिंग करना।

--8--

✂ न्यूज़ इन शॉर्ट्स ⚡

क्र. सं.	न्यूज़
1.	<p>राजस्थान स्पोर्ट्स एक्ट, 2005 में संशोधन हेतु ड्राफ्ट जारी</p> <ul style="list-style-type: none">हाल ही में, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान स्पोर्ट्स एक्ट, 2005 में संशोधन हेतु ड्राफ्ट जारी किया गया।संशोधन से नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड की तरह राजस्थान स्पोर्ट्स बोर्ड का गठन किया जाएगा, जिससे खेल संघों पर रजिस्ट्रार की बजाय बोर्ड का नियंत्रण बढ़ेगा।वर्तमान में खेल संघों के पंजीकरण की शक्ति रजिस्ट्रार के पास होती है, संशोधन के बाद यह अधिकार राजस्थान स्पोर्ट्स बोर्ड को मिल सकेगा।
2.	<p>चर्चा में - T-2408</p> <ul style="list-style-type: none">हाल ही में, रणथंभौर टाइगर रिज़र्व (सवाई माधोपुर) के T-2408 बाघ को मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिज़र्व (कोटा) में स्थानांतरित किया गया।रणथंभौर टाइगर रिज़र्व से अब तक 24 बाघ-बाघिन को अन्य टाइगर रिज़र्व में शिफ्ट किया जा चुका है।

3.

सशस्त्र ड्रोन - 'प्रलय'



- जयपुर में आयोजित 78वें सेना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत 'नो योर आर्मी' प्रदर्शनी में 'प्रलय ड्रोन' को भी प्रदर्शित किया गया है।
- प्रदर्शनी में प्रदर्शित प्रलय ड्रोन 2 किलोग्राम की पेलोड क्षमता के साथ 30 से 40 मिनट की उड़ान अवधि में अधिकतम 4 किलोमीटर तक की दूरी तय करने में सक्षम है।
- यह ड्रोन अधिकतम 300 मीटर की ऊँचाई पर उड़ान भरते हुए लक्ष्य पर सटीक प्रहार कर सकता है।
- **नोट :** 'प्रलय मिसाइल' का विकास डिफेंस रिसर्च एंड डवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (DRDO) द्वारा किया गया है जो शॉर्ट-रेंज क्वासी-बैलिस्टिक मिसाइल है।

--:10:--

4.	<p>क्षुद्रग्रह (2021 DB5) का नया नाम - प्रमिश्का</p> <ul style="list-style-type: none">■ नामकरण : झालावाड़ के पिपलोदी में स्कूल की इमारत ढहने से जान गंवाने वाले 7 बच्चों की स्मृति में क्षुद्रग्रह (2021 DB5) का नाम 'प्रमिश्का' रखा जाएगा।■ प्रस्तावित नाम 'प्रमिश्का' 7 दिवंगत बच्चों - पायल, प्रियंका, मीना, हरीश, कुंदन, कान्हा और सतीश के नामों के शुरुआती अक्षरों को जोड़कर बनाया है।■ खोज : ज्ञातव्य है कि झालावाड़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, उन्हेल की सुगंधा कुमारी, कोमल कंवर, हर्षिता डांगी और संजय कुमार ने वर्ष 2020-21 में 4 क्षुद्रग्रहों की खोज की थी।■ नासा द्वारा मान्यता प्राप्त : खोजे गए 4 क्षुद्रग्रहों को नासा (अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी) द्वारा परमानेंट नंबर अलॉट किया जा चुका है।
5.	<p>निशानेबाज स्वीटी चौधरी</p> <ul style="list-style-type: none">■ राजस्थान की शूटर स्वीटी चौधरी ने भोपाल में सम्पन्न 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप (राइफल इवेंट्स) में एक स्वर्ण पदक और दो कांस्य पदक जीते।■ सीनियर महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा में राजस्थान की टीम (मनीनी कौशिक, स्वीटी चौधरी और मोनिका जाखड़) ने 1751 अंकों के साथ स्वर्ण पदक जीता।
6.	<p>सब लेफ्टिनेंट रक्षिता राठौड़</p> <ul style="list-style-type: none">■ सब लेफ्टिनेंट रक्षिता राठौड़ भारतीय नौसेना में तकनीकी अधिकारी बनने वाली राजस्थान की पहली महिला है।■ कंप्यूटर साइंस में बीटेक रक्षिता राठौड़ मूल रूप से नागौर की निवासी है।
7.	<p>ईशविंदर सिंह : FIGSI के नए अध्यक्ष</p> <ul style="list-style-type: none">■ जयपुर निवासी ईशविंदर सिंह को हाल ही में तीसरी बार 'फेडरेशन ऑफ इंडियन ग्रेनाइट एंड स्टोन इंडस्ट्री (FIGSI)' का अध्यक्ष चुना गया।■ उनका कार्यकाल वर्ष 2026 से 2028 तक रहेगा।



राष्ट्रीय परिदृश्य



भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI): उदय शुभंकर

चर्चा में क्यों?

- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार से संबंधित जानकारी को अधिक सुलभ और लोगों के अनुकूल बनाने के लिए आधार शुभंकर 'उदय' लॉन्च किया।

मुख्य बिन्दु:

- **परिचय:** यह आधार सेवाओं (अपडेड, प्रमाणीकरण, ऑफलाइन सत्यापन, डेटा साझाकरण) के संचार को सरल बनाने के लिए डिज़ाइन किया है।
- **संबंधित संगठन:** भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI)
- **उद्देश्य:** आधार संचार को सरल, मानवीय और मानकीकृत बनाना, भागीदारी के माध्यम से नागरिकों का विश्वास बढ़ाना और एक अरब से अधिक निवासियों के लिए इसकी पहुँच में सुधार करना।



महत्त्व:

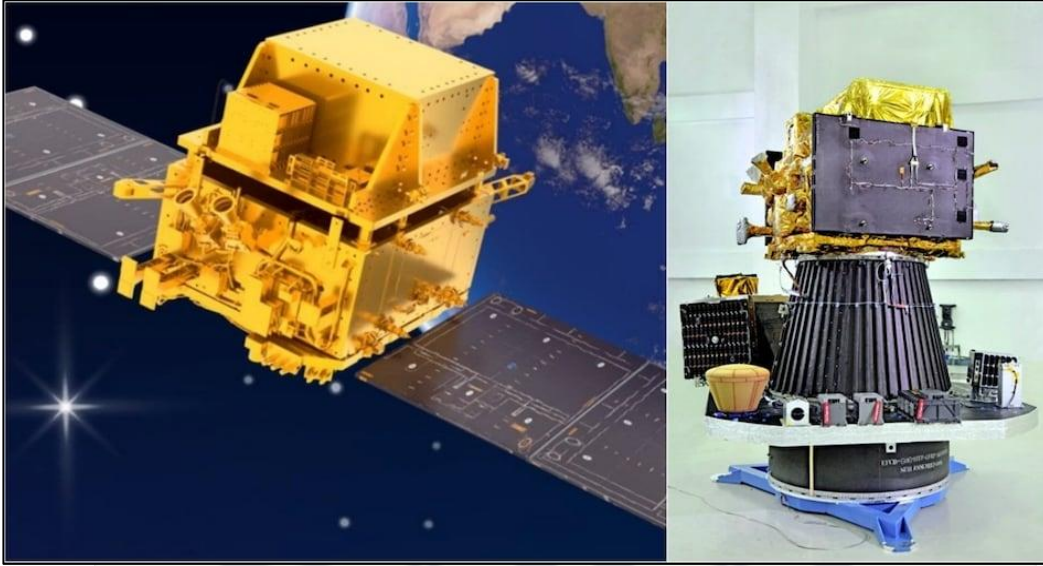
1. विश्वास और स्वीकृति।
2. बेहतर सेवा वितरण।
3. डिजिटल सार्वजनिक क्षेत्र में नागरिक सहभागिता।

⌚ विज्ञान प्रौद्योगिकी ⌚

पृथ्वी अवलोकन उपग्रह: EOS-N1 (अन्वेषा)

📢 चर्चा में क्यों?

- 12 जनवरी, 2026 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा PSLV-C-62 मिशन का प्रक्षेपण करेगा।



📌 मुख्य बिन्दु:

- परिचय: EOS-N1 (अन्वेषा) एक उन्नत हाइपरस्पेक्ट्रल पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है।
- प्रक्षेपण: 12 जनवरी, 2026 को श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र।
- प्रक्षेपण यान : PSLV- C-62
- मिशन पेलोड : इसमें मुख्य भारतीय पेलोड पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-N1 सहित अन्य देशों के 18 उपग्रह भी प्रेषित किए जाएँगे।

कार्य:

1. हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग: अनेक स्पेक्ट्रल बैंड (सटीकता)।
2. रणनीतिक निगरानी: सीमा निगरानी, भू-भाग विश्लेषण, राष्ट्रीय सुरक्षा की मजबूती।
3. कृषि सहायता: फसल स्वास्थ्य मूल्यांकन, मृदा नमी व उपज अनुमान।
4. शहरी और अवसंरचना मानचित्रण व पर्यावरण निगरानी।

रेबीज: अधिसूचित बीमारी (नोटिफायबल डिजीज) घोषित

चर्चा में क्यों?

- दिल्ली सरकार ने कुत्तों के काटने से होने वाली रेबीज से मानव मृत्यु दर को शून्य करने के उद्देश्य से, मानव रेबीज को महामारी रोग अधिनियम, 1897 के तहत अधिसूचित करने योग्य बीमारी घोषित किया है।

RABIES Zero deaths by 2030

99% human cases result from dog bites

One death every 9 minutes worldwide

4 out of 10 deaths are in children

100% vaccine preventable

no bite no rabies

VACCINATE TO STOP TRANSMISSION

VACCINATE TO SAVE LIVES

learn how to interact

#rabies 28 September World Rabies Day

www.who.int/rabies/en

World Health Organization

मुख्य बिन्दु:

- अधिसूचित बीमारी : वह रोग जिनकी सूचना सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों को देना कानूनी रूप से अनिवार्य है। रोग निगरानी का प्रमुख ढाँचा एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (IDSP) है, जिसका संचालन राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) द्वारा किया जाता है।

Daily Current Affairs

Date : 10 January, 2026



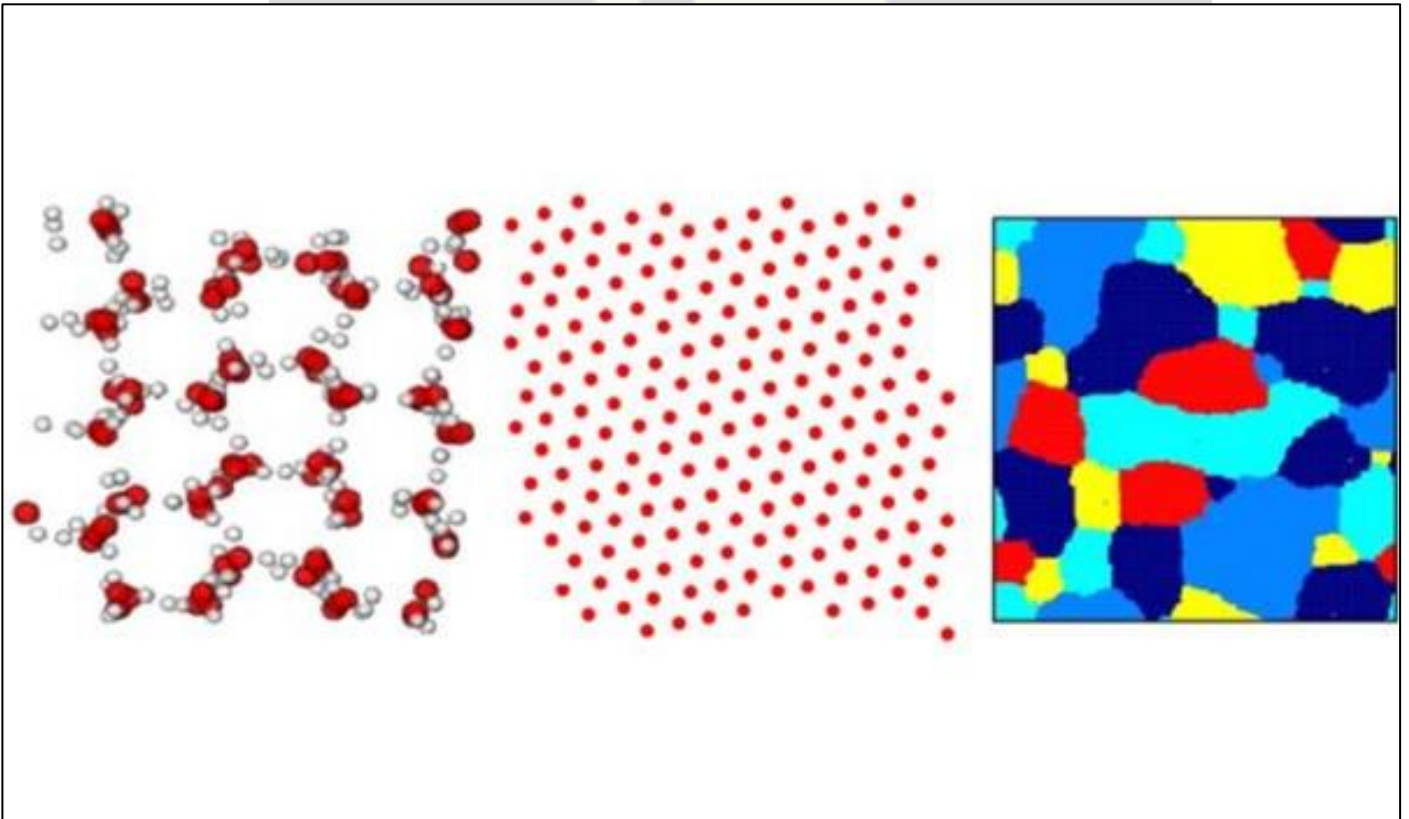
- **अधिसूचना का प्रभाव :** एक बार अधिसूचित रोग घोषित होने के बाद सभी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता, अस्पताल और चिकित्सा व्यवसायी संदिग्ध, संभावी और पुष्ट मामलों की रिपोर्ट नामित अधिकारियों को देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होते हैं।
 - **अधिसूचित रोग:** राज्यों के अनुसार सूचियाँ भिन्न-भिन्न होती है। कुछ प्रमुख अधिसूचित रोग; तपेदिक, डेंगू, मलेरिया, हैजा, हेपेटाइटिस, खसरा और पोलियो आदि।
 - **NOTE :** कोविड-19 को महामारी के दौरान सार्वभौमिक रूप से अधिसूचित किया गया था।
 - वर्ष 2024 में सांप के काटने को भी अधिसूचित बीमारियों में शामिल किया गया।
 - यह विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (वर्ष 2005) के तहत कानूनी रूप से बाध्यकारी है।
- अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु:**
- रेबीज:**
- रेबीज एक घातक वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से RNA वायरस के कारण होता है।
 - **संक्रमण का स्रोत:** संक्रमित कुत्ते, बिल्ली, बंदर या नेवले के काटने, खरोंचने या उनकी लार के किसी खुले घाव के संपर्क में आने से।
 - **प्रभाव:** यह वायरस सीधे इंसान के सेंट्रल नर्वस सिस्टम (ब्रेन) पर हमला करता है।

--:15:--

सुपरकंप्यूटर संचालित पहला सिमुलेशन

चर्चा में क्यों?

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र के वैज्ञानिकों ने पेंबा प्रभाव (Mpemba Effect) की व्याख्या के लिए सुपरकंप्यूटर आधारित पहली सिमुलेशन विकसित की है।



मुख्य बिन्दु:

पेंबा प्रभाव (Mpemba effect) :

- सर्वप्रथम खोज: अरस्तू
- पुनः खोज: एरास्तो पेंबा
- परिचय: यह वह परिघटना है, जिसमें अधिक उष्ण जल कम उष्ण (शीत) जल की तुलना में तेजी से जम जाता है।

Daily Current Affairs

Date : 10 January, 2026



जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र (JNCASR) के अध्ययन का निष्कर्ष :

- **अध्ययन:** अध्ययन से ज्ञात होता है कि जल सीधे नहीं जमता है, बल्कि यह अधिक मध्यवर्ती आप्विक अवस्थाओं से होकर गुजरता है।
- अधिक उष्ण जल कभी-कभी इस विलंब को पार कर हिमीकरण की प्रक्रिया तक तेजी से पहुँच सकता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि क्यों उष्ण जल कभी-कभी पहले जम जाता है।
- **निष्कर्ष:** पेंबा प्रभाव वास्तविक है और यह केवल जल तक सीमित नहीं है, क्योंकि यह अन्य तरल से ठोस अवस्था परिवर्तन में भी देखा जा सकता है।

UTKARSH

CIVIL
SERVICES

-:17:-

आर्थिक परिदृश्य

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय : सकल घरेलू उत्पाद अनुमान

चर्चा में क्यों?

- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जारी सकल घरेलू उत्पाद के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत की वास्तविक GDP में 7.4% वृद्धि होगी।

मुख्य बिन्दु:

- वित्त वर्ष 2025-26 में वास्तविक GDP में 7.4% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में यह वृद्धि दर 6.5% थी।
- वित्तवर्ष 2025-26 में नॉमिनल GDP में 8% की वृद्धि का अनुमान है।
- सेवा क्षेत्र में हुई तेज वृद्धि को वित्तवर्ष 2025-26 में अनुमानित 7.3% की वास्तविक GVA वृद्धि में एक प्रमुख कारक माना गया है।
- तृतीयक क्षेत्र में वित्तीय, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाएँ तथा लोक-प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाओं के वित्त वर्ष 2025-26 में स्थिर कीमतों पर 9.9% की पर्याप्त वृद्धि दर का अनुमान है।
- द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण और निर्माण क्षेत्र के लिए वित्त वर्ष 2025-26 में स्थिर कीमतों पर 7.5% वृद्धि दर का अनुमान है।
- कृषि व संबद्ध क्षेत्र (3.1%), बिजली, गैस, जल आपूर्ति एवं अन्य उपयोगिता सेवा क्षेत्र (2.1%), वास्तविक निजी अंतिम उपभोग व्यय (7%)।

Daily Current Affairs

Date : 10 January, 2026



- **NOTE :** वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान स्थिर कीमतों पर सकल स्थिर पूँजी निर्माण (GFCF) की वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में यह वृद्धि दर 7.1% थी।

अन्य महत्त्वपूर्ण बिन्दु:

भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि का अनुमान: संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट:

- वर्ष 2026 भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 6.6 प्रतिशत और अगले वर्ष 6.7 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है।
- कारण: कर सुधार और मौद्रिक नीति में परिवर्तन।

UTKARSH

CIVIL
SERVICES

-:19:-

महत्त्वपूर्ण पोर्टल एवं एप

पंखुड़ी पोर्टल

चर्चा में क्यों?

- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पंखुड़ी नामक एक एकीकृत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) और साझेदारी की सुविधा डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया।



मुख्य बिन्दु:

- **परिचय:** पंखुड़ी को सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है, जो महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों, अनिवासी भारतीय (NRI), गैर-सरकारी संगठनों (NGO), कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) योगदानकर्ताओं, कॉर्पोरेट संस्थाओं और सरकारी एजेंसियों को एक साथ एक मंच पर लाता है।
- **शुभारंभ:** 8 जनवरी, 2026

--:20:--

Daily Current Affairs

Date : 10 January, 2026



- **उद्देश्य:** महिला एवं बाल विकास पहलों में समन्वय, पारदर्शिता और हितधारकों की सुनिश्चितता को सुदृढ़ करना।
- **मंत्रालय:** महिला एवं बाल विकास मंत्रालय।

मुख्य विशेषताएँ:-

1. एकीकृत CSR इंटरफेस।
2. प्राथमिकता वाले विषय: पोषण, स्वास्थ्य, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ECCE), बाल कल्याण और संरक्षण, महिलाओं की सुरक्षा व सशक्तीकरण।
3. प्रमुख मिशनों को समर्थन; सक्षम आँगनबाड़ी मिशन, पोषण 2.0, मिशन वात्सल्य, मिशन शक्ति इत्यादि।

UTKARSH

CIVIL
SERVICES

-:21:-



महत्त्वपूर्ण दिवस



विश्व हिंदी दिवस, 2026: 10 जनवरी



मुख्य बिन्दु:

तिथि	10 जनवरी, 2026
वर्ष 2026 की थीम	“हिंदी: पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक”
कारण	10 जनवरी, 1975 को नागपुर में आयोजित प्रथम विश्व हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में।
आधिकारिक घोषणा	वर्ष 2006 (प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में।)
हिंदी का महत्त्व	वैश्विक मान्यता: तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है।
संवैधानिक स्थिति	1. अनुच्छेद-343: भारत संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी है। 2. अनुसूची-8: 22 भाषाओं में सूचीबद्ध।



जिन्सन जॉनसन : भारतीय धावक

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता और भारतीय धावक जिन्सन जॉनसन ने संन्यास की घोषणा की।




मुख्य बिन्दु:

- संबंध : केरल

उपलब्धियाँ:

- वर्ष 2018 जकार्ता एशियाई खेलों में 1500 मीटर में स्वर्ण पदक जीता तथा इन्हीं खेलों में 800 मीटर में रजत पदक भी जीता था।
- वर्ष 2018 में गुवाहाटी में राष्ट्रीय अंतर-राज्यीय चैंपियनशिप में श्रीराम सिंह का 42 वर्ष पुराना पुरुषों का 800 मीटर राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा था।
- ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में जॉनसन ने 23 वर्ष पुराना 1500 मीटर राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा, हालांकि वह फाइनल में 5 वें स्थान पर रहे।
- जॉनसन ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड में 2 बार सुधार किया।
- सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन** : वर्ष 2019 में बर्लिनमीट के समय 3 मिनट 35 दशमलव दो चार सेकेंड।

✂ न्यूज़ इन शॉर्ट्स ⚡

क्र. सं.	न्यूज़
1.	<p>सुरेश कलमाड़ी: निधन</p>  <ul style="list-style-type: none">■ पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाड़ी का निधन हो गया।■ कलमाड़ी ने भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया।■ कलमाड़ी, पूर्व प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव के कार्यकाल में रेल राज्यमंत्री रहे थे।■ इन्होंने पूणे से संसद में प्रतिनिधित्व किया।